फोनः-4103333, 2362400 फैक्सः-0141-2373513 वर्षः 77 संख्याः 91 प्रभात जयपुर, शनिवार 31 अक्टूबर, 2026 डाक पं.सं. जयपुर सिटी/001/2021-23 पृष्ठ 8 मूल्य 2.75 रु.

ARBiT

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

epaper.rashtradoot.com

राष्ट्रदूत

Metro

Rashtradoot



A Release And A Farewell

Hermann Ritter was unlikely to kill the only man who knew how to navigate the dog team back to safety. He had done his duty, but was privately glad for a way out of a war he disapproved of

This Hindi Word Rewrote the Rules of Innovation

देशों के संबंध राष्ट्राध्यक्षों की ''पर्सनल कैमिस्ट्री'' पर आधारित होना भारी पड़ सकता है

भारत और इज़रायल के संबंध पूरी तरह से प्र.मंत्री मोदी की इज़रायल के राष्ट्र प्रमुख नेतन्याहू के साथ ''पर्सनल कैमिस्ट्री पर आधारित हैं

- लेकिन इज़रायल में अब नेतन्याहू की सत्ता जाने का खतरा है और उनके प्रतिद्वंदी की प्र.मंत्री मोदी के साथ खास नज़दीकी नहीं है। ऐसे में भारत-इज़रायल रिश्ते में मिठास कुछ कम होने का खतरा है।
- नेतन्याहू के लंबे कार्यकाल में भारत व इज़रायल के बीच व्यापारिक एवं रक्षा संबंधों में काफी मजबूती आई और भारत ने भारी मात्रा में इज़रायल से हथियार व अन्य रक्षा उपकरण खरीदे थे।

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 30 अक्टूबर। गठबंधन को लेकर बातचीत के बीच बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में बने रहने की संभावना है। वे दोबारा सत्ता संभालने की दौड़ से पूरी तरह बाहर नहीं हुए हैं, लेकिन इस महीने हुए चुनाव के बाद उनकी स्थिति काफी कमजोर हो गई है। अहम सवाल यह है कि भारत और इज़रायल के संबंधों में क्या कोई बदलाव होने की संभावना है?

इज़रायल की 120 सदस्यों वाली संसद (नेसेट) में नेतन्याहू के दक्षिणपंथी गठबंधन को लगभग 53 सीटें मिलीं, जो बहुमत से कम हैं। वहीं, गादी आइज़ेनकोट के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन को करीब 48 सीटें मिलीं, जबकि अरब पार्टियों ने 19 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया।

नेतन्याहू और भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बीच काफी करीबी संबंध रहे हैं। मोदी की 2017 की इज़रायल यात्रा किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली इज़रायल यात्रा थी। इसके जवाब में नेतन्याहू ने भी भारत का दौरा किया था। मोदी ने फरवरी 2026 में फिर इज़रायल का दौरा किया, वहां की संसद (नेसेट) को संबोधित किया और दोनों देशों के संबंधों को ''विशेष रणनीतिक साझेदारी'' (स्पैशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप) का दर्जा दिया। नेतन्याहू सार्वजनिक रूप से मोदी को अपना ''भाई'' और ''बहुत अच्छा मित्र'' बता चुके हैं। दोनों नेताओं के बीच नियमित संपर्क बना हुआ है। 22 अक्टूबर 2026 को भी दोनों के बीच फोन पर बातचीत हुई, जिसमें उन्होंने अपनी द्विपक्षीय साझेदारी को फिर से दोहराया। दोनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और राष्ट्रवादी शासन पर समान जोर दिया।

नेतन्याहू के लंबे कार्यकाल के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार और रक्षा सहयोग में काफी विस्तार हुआ। भारत इज़रायल से हथियार खरीदने वाला सबसे बड़ा देश बन गया। सन् 2021 से 2025 के दौरान इज़रायल के कुल रक्षा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी लगभग 29 प्रतिशत रही। इसमें ड्रोन, मिसाइल प्रणालियां, निगरानी उपकरण और उनसे जुड़ी तकनीक शामिल हैं। दोनों देशों के बीच 1990 के दशक के बाद से व्यापार में काफी वृद्धि हुई है। रक्षा के अलावा कृषि, जल प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) तथा साइबर सुरक्षा जैसे नए क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ा है।

सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के अनुसार, मोदी और गादी आइज़ेनकोट के बीच पहले से कोई खास व्यक्तिगत तालमेल या घनिष्ठ संबंध नहीं रहा है। आइज़ेनकोट 2015 से 2019 तक इज़रायल की सेना के प्रमुख रह चुके हैं। वे ''यशार'' पार्टी का नेतृत्व करते हैं। वे सुरक्षा के लिए जवाबदेही तथा 7 अक्टूबर की घटनाओं के बाद सुधारों की मांग को

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की वृद्धि

- राजस्थान सरकार ने कर्मचारियों को तदर्थ बोनस की भी घोषणा की।

जयपुर, 30 अक्टूबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दीपावली के अवसर पर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी सौगात दी है। राज्य सरकार ने सातवें वेतनमान के तहत महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में 3 प्रतिशत वृद्धि को मंजूरी दी है। इसके बाद डीए-डीआर की दर 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगी। सरकार के इस फैसले से 7 लाख से अधिक कर्मचारी और 5 लाख से अधिक पेंशनर्स लाभान्वित होंगे। इसके साथ ही, करीब 6 लाख पात्र कर्मचारियों को तदर्थ बोनस भी दिया जाएगा।

महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से चालू वित्त वर्ष में सरकार पर करीब 820 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा।

राज्य सरकार ने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के साथ तदर्थ बोनस का भी उपहार दिया है। इसके तहत, पे-मैट्रिक्स लेवल एल-12 या उससे कम अथवा 4800 रुपए या उससे कम ग्रेड पे वाले करीब 6 लाख कर्मचारियों को बोनस मिलेगा। इस पर सरकार 406 करोड़ रुपए खर्च करेगी। बोनस की 75 प्रतिशत राशि नकद दी जाएगी, जबकि शेष 25 प्रतिशत कर्मचारियों के जीपीएफ खातों में जमा होगी।

बारिश के कारण ''पोस्टपोन'' हुआ ज्ञानेश कुमार का महाभियोग कार्यक्रम

विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कार्यक्रम ''पोस्टपोन'' होने की पुष्टि की और कहा कि अब यह कार्यक्रम शनिवार 4 बजे होगा

- यह महाभियोग, विपक्ष का, वोट चोरी के खिलाफ प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन है।
- सूत्रों ने कहा कि पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार कार्यवाही की अध्यक्षता करेंगी। खड़गे प्रस्ताव रखेंगे और राहुल गांधी इस पर टिप्पणी करेंगे।

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 30 अक्टूबर। राजधानी में बारिश के कारण विपक्षी गठबंधन को शुक्रवार दोपहर को होने वाला कार्यक्रम शनिवार के लिए टालना पड़ा। शुक्रवार सुबह से ही राजधानी में लगातार हो रही बारिश की वजह से ''सार्वजनिक महाभियोग'' कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ा। यह कार्यक्रम मध्य दिल्ली के राजाजी मार्ग स्थित कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सरकारी आवास के लॉन में दोपहर 3:30 बजे आयोजित होना था।

अब यह कार्यक्रम शनिवार को आयोजित किया जाएगा।

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि कार्यक्रम शनिवार तक टाल दिया गया है। गांधी ने कहा, ''हम सभी ने मिलकर फैसला किया है कि जनता द्वारा महाभियोग का कार्यक्रम शनिवार शाम 4 बजे आयोजित किया जाएगा।'' सूत्रों के अनुसार, लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष मीरा कुमार इस पूरी कार्यवाही की अध्यक्षता करेंगी। खड़गे इस दौरान ''प्रस्ताव'' पेश करेंगे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी समापन भाषण देंगे।

वोट चोरी के मुद्दे पर प्रतीकात्मक विरोध जताने के लिए इंडिया गठबंधन के नेताओं ने गुरुवार को बैठक की थी। इस बैठक में ''जनता द्वारा महाभियोग'' की पूरी कार्यवाही को अंतिम रूप दिया गया। गुरुवार को हुई तैयारी बैठक में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, जयराम रमेश और के. सी. वेणुगोपाल, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता मीरा कुमार, तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ' ब्रायन, समाजवादी पार्टी के हरेन्द्र मलिक, झारखंड मुक्ति मोर्चा की महुआ माजी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जॉन ब्रिटास सहित, कई नेताओं ने हिस्सा लिया।बैठक में फैसला किया गया कि इस कार्यक्रम को मॉक पार्लियामेंट (नकली संसद) नहीं कहा जाएगा, जैसा कि शुरुआत में सुझाव दिया गया था।

राफेल मरीन की आईएनएस विक्रांत पर सफल लैंडिंग

नई दिल्ली, 30 अक्टूबर। 29 अक्टूबर को फ्रांसीसी लड़ाकू विमान राफेल मरीन ने भारत के पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत पर पहली बार सफल लैंडिंग की। खास बात यह रही कि यह लैंडिंग अपने पहले

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'भविष्य के लिए पैसा बचाना बेमानी हो सकता है'

एलन मस्क ने कहा, आर्टिफिशल इंटैलिजैंस से ऐसा समय आ सकता है, जब पैसे का महत्व ही खत्म हो जाएगा

- मस्क ने एआई के कारण रोजगार खत्म होने की संभावना पर युनिवर्सल हाई इन्कम का प्रस्ताव रखा, जिसके तहत सरकारें सीधे नागरिकों को पैसा देंगी।
- मस्क ने कहा कि एआई और रोबोटिक्स में प्रगति से अर्थव्यवस्था के काम करने के तरीके में बुनियादी रूप से बदलाव आ सकता है।

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 30 अक्टूबर। एलन मस्क का कहना है कि भविष्य में पैसा बचाकर रखना ''बेमानी'' हो सकता है, क्योंकि आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) की वजह से एक समय ऐसा आ सकता है, जब पैसे का महत्व ही खत्म हो जाए।

टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ और अरबपति मस्क का मानना है कि आर्टिफिशल इंटेलिजेंस और रोबोट भविष्य में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की लागत इतनी कम कर सकते हैं कि भविष्य के लिए बचत करने की जरूरत नहीं रह जाएगी। उन्होंने एआई के कारण रोजगार खत्म होने की आशंका से निपटने के लिए सरकार की ओर से ''यूनिवर्सल हाई इनकम'', यानी सभी नागरिकों को पर्याप्त आय देने का प्रस्ताव भी रखा है।

क्या हो, अगर आपकी खरीदारी की कुछ गलत आदतें वास्तव में गलत न हों, क्योंकि आने वाले कुछ वर्षों में पैसे का महत्व ही खत्म हो जाए? एलन मस्क ने इस सोच के समर्थन में एक दिलचस्प तर्क दिया है। उनका मानना है कि आर्टिफिशल इंटेलिजेंस लगभग हर चीज को सस्ता बना सकती है।

मस्क की यह टिप्पणी एक्स के एक यूज़र की पोस्ट के बाद आई। इस यूज़र ने भविष्य में समृद्धि आने की उम्मीद का

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

25 जनवरी से शुरु होगी जनगणना

- यह भारत की पहली डिजिटल जनगणना है। इसमें 10 से 24 जनवरी तक व्यक्ति खुद भी पोर्टल पर डेटा भर सकेंगे।

नई दिल्ली, 30 अक्टूबर। देश में लंबे समय से इंतजार की जा रही जनगणना को लेकर सरकार ने तारीखों का एलान कर दिया है। भारत में जनगणना 2027 की प्रक्रिया 25 जनवरी से 28 फरवरी 2027 तक कराई जाएगी। इस दौरान देशभर में आबादी की गिनती की जाएगी। लेकिन चुनाव वाले और बर्फ से प्रभावित राज्यों को इस प्रक्रिया से छूट दी गई है।

5 राज्यों-मणिपुर, गोवा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड को छोड़कर पूरे देश में जनगणना होगी। इन राज्यों में 2027 की शुरुआत में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'आर यू में पीएचडी भर्ती परीक्षा में मनमाने तरीके से जारी मेरिट लिस्ट खारिज करें'

राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि उच्च शिक्षा विभाग ने मैरिट लिस्ट जारी करते समय यूजीसी द्वारा पीएचडी प्रोग्राम में भर्ती के मापदंड व परीक्षा प्रक्रिया को नहीं अपनाया

- इस मामले में यश चंद्रा की ओर से याचिका दायर की गई थी, जो अर्थशास्त्र विभाग में जूनियर रिसर्च फैलोशिप के पद पर नियुक्त होने के लिए 2026 अगस्त माह में आयोजित इंटरव्यू में भाग ले चुके थे, परंतु उन्हें मैरिट लिस्ट में जगह नहीं मिली।

-यादवेन्द्र शर्मा-

जयपुर, 30 अक्टूबर। राजस्थान यूनिवर्सिटी में ''पी.एच.डी.एडमिशन'' परीक्षा की मैरिट लिस्ट तय नियमों के अनुसार जारी नहीं करने और मैरिट लिस्ट में उपयुक्त अभ्यार्थी को जगह नहीं मिलने से संबंधित मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिस पर अदालत ने आदेश दिये कि प्रशासन व राजस्थान यूनिवर्सिटी के अधिकारी उपयुक्त अभ्यार्थियों को पी.एच.डी. एडमिशन परीक्षा की मैरिट लिस्ट में जोड़ने के लिए पुन: विचार करें और मैरिट लिस्ट ''यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन'' (यूजीसी) के नियमों के अनुसार ही जारी की जाए। न्यायाधीश समीर जैन के एकलपीठ ने यह आदेश यश चंद्रा व अन्य दो याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिये। इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता दर्श पारीक पैरवी के लिए पेश हुए थे, इसके अलावा अदालत ने अधिवक्ता रूद्रांशू सिंह को न्याय मित्र घोषित किया था।

इस मामले के तथ्य के अनुसार, याचिकाकर्ता यश चंद्रा व अन्य ने वर्ष 2025-26 के शैक्षणिक सत्र में आयोजित आर यू की ''पी.एच.डी.एडमिशन'' परीक्षा (रूपा) में भाग लिया था। याचिकाकर्ता यश चंद्रा ''रूपा'' ने परीक्षा के तहत ''जूनियर रिसर्च फैलोशिप'' (जे.आर.एफ.) के पद के लिए चयनित

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)